प्रेस विज्ञप्ति

06 दिसंबर, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी; श्रीमति प्रियंका चतुर्वेदी, कन्वीनर, संचार विभाग व श्री पवन खेडा ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

"परिवहन सेवाओं में वित्तीय कुप्रबंधन तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला"

"22 साल में रोडवेज सेवा में 100% कटौती, परंतु करोडों सब्सिडी/नुकसान में गंवाए"

"बेशकीमती सरकारी जमीन का व्यवसायीकरण कर जनता को चूना लगाया"

"परिवहन सेवाओं में प्रतिदिन, ₹ 1,11,60,555 यानि ₹ 7050 प्रति मिनट का नुकसान"

22 वर्ष के भाजपाई कुशासन में हर मौके पर सरकार अपनी परंपरागत जवाबदेही व मूलभूत सेवाएं प्रदान करने से पीछा छुड़ाती आई है। बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन के क्षेत्रों में 6.5 करोड़ गुजरातियों के प्रति सुविधाएं प्रदान करने की जवाबदेही से भाजपा सरकार कोसों दूर है। उल्टा इन सभी क्षेत्रों में "**निजीकरण**" ही एकमात्र भाजपाई नीति बन गई है। वित्तीय कुप्रबंधन, गड़बड़झाला व भ्रष्टाचार के अनेकों उदाहरणों ने सरकार की पोल खोल दी है।

एक सुनियोजित साजिश के चलते सरकार द्वारा संचालित परिवहन सेवाओं में न केवल 100 प्रतिशत कटौती कर दी गई, परंतु हजारों करोड़ के राजस्व का इस्तेमाल सब्सिडी देने व नुकसान उठाने में लगा दिया। गुजरात की जनता अब जवाबदेही मांगती है।

1. गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (जीएसआरटीसी)

साल	शेड्यूल (चल रही बसों की संख्या)	ट्रिप्स
1994	7,853	70,442
2017	6,943	44,700

22 वर्षों के बाद बढ़ती जरूरत और जनसंख्या के चलते बसों की संख्या व ट्रिप्स 4/5 गुना बढ़ जानी चाहिए थी। भाजपाई दुर्भावना के चलते बसों की संख्या भी कम हो गई और ट्रिप्स भी आधी रह गई। क्या श्री नरेंद्र मोदी/श्री अमित शाह/श्री विजय रूपानी जवाब देंगे?

2. 1994 तक कांग्रेस शासन तक सरकारी बसें गुजरात के 18,225 गांव यानि प्रत्येक गांव तक पहुंचती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों की अवहेलना के चलते आज सरकारी बसें 9000 गांव तक भी पूरी मात्रा में नहीं पहुंच रहीं। क्या श्री नरेंद्र मोदी/श्री अमित शाह/श्री विजय रूपानी जवाब देंगे?

3. गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (जीएसआरटीसी)

साल	अर्जित नुकसान
1960 से 1994–95	389 करोड़
1996–97 से 2016–17	2,971 करोड़

35 साल में (1960 से 1994–95) मात्र 389 करोड़ का नुकसान। बसें कम होने व ट्रिप्स आधी रह जाने के बावजूद ₹ 2,971 करोड़ का नुकसान। ऐसा क्यों? आश्चर्य की बात तो यह है कि साल 2016–17 में गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ₹401.78 करोड़ का नुकसान हुआ। यानि कि हर रोज ₹1,11,60,555 का नुकसान। इसका मतलब है कि गुजरात के लोगों को हर मिनट ₹7,750 का नुकसान, परंतु सेवा कोई नहीं। क्या श्री नरेंद्र मोदी/श्री अमित शाह/श्री विजय रूपानी जवाब देंगे?

4. गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को दी जाने वाली बेतहाशा सब्सिडी से सरकारी खजाने को हानि, परंतु जनता को रत्तीभर लाभ नहीं। 1995–96 से 2016–17 के बीच में गुजरात सरकार ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ₹8,263 करोड़ की सब्सिडी दी। इसके बावजूद भी परिवहन सेवाएं यानि ट्रिप्स आधी क्यो रह गई? क्या इससे वित्तीय कुप्रबंधन साफ तौर से नजर नहीं आता। क्या श्री नरेंद्र मोदी/श्री अमित शाह/श्री विजय रूपानी जवाब देंगे?

5. यहां तक कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की संख्या भी 22 साल में गिरकर कम हो गई। 1994–95 में जीएसआरटीसी के कर्मचारियों की संख्या 55 हजार थी, जो 2016–17 में कम होकर लगभग 40 हजार रह गई। ऐसा क्यों?

6. यहां तक कि सरकारी बस अड्डों की महंगी व्यवसायिक जमीन को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप/बीओटी के माध्यम से दे दिया गया, परंतु जनता को उसका रत्तीभर भी लाभ नहीं हुआ। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं :–

शहर का नाम	बस अड्डे का नाम	प्राईवेट कंपनी का नाम
अहमदाबाद	गीता मंदिर बस स्टेशन	एचयूबी कंपनी
अहमदाबाद	रानिप बस स्टेशन	एएआरवीईबी
वडोदरा	रेस कोर्स बस स्टेशन	एएआरवीईबी
वडोदरा	मक्करपुरा बस स्टेशन	एचयूबी कंपनी
मेहसाणा	मेहसाणा बस स्टेशन	एचयूबी कंपनी

वाणिज्यिक जमीन के बदले में ये निजी कंपनियों केवल बस अड्डे की मेंटेनेंस, बिजली और पानी के लिए जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि क्या इससे आम जनमानस को कोई लाभ हुआ? सरकार के खजाने में कितना पैसा आया? क्या यह संयोग है कि पांचों बस स्टेशन केवल दो ही प्राईवेट कंपनियों को मिले? क्या श्री नरेंद्र मोदी/श्री अमित शाह/श्री विजय रूपानी जवाब देंगे?

गुजरात मांगे जवाब, गुजराती मांगे जवाबदेही